



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7]
No. 7]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 10, 2000/पौष 20, 1921
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 10, 2000/ PAUSA 20, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2000

सं. टीएएमपी/1/98-वीपीटी.— महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने विशाखापट्टनम पत्तन न्यास (वीपीटी) में मैंगनीज अयस्क के प्रहस्तन के बारे में मैसर्स एस.के. सारावागी एंड कं. (प्रा.) लिमिटेड और मैसर्स राम बहादुर ठाकुर लिमिटेड से संबंधित मामला सं. टीएएमपी/1/98-वीपीटी में एक आदेश पारित किया था। यह आदेश गजट संख्या 112 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग-III, खंड-4) में दिनांक 31-12-99 को अधिसूचित किया गया था।

2. आदेश के पैराग्राफ संख्या 22.1 में मुद्रण संबंधी एक त्रुटि रह गई है। पैराग्राफ के अंतिम वाक्य में ब्याज की दर "12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर" के स्थान पर "24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर" दी गई है। इसलिए पैराग्राफ संख्या 22.1 के अंतिम वाक्य को हटाया जाता है और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"वीपीटी को आवेदकों के मामलों में तदनुसार प्रहस्तन लक्षित करके प्रकलन करना है और 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित आवश्यक वापसी करनी है, जैसाकि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है।"

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/143/99]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th January, 2000

No. TAMP/1/98-VPT.— The Tariff Authority for Major Ports had passed an Order on 8 December, 99 in case No. TAMP/1/98-VPT about handling of Manganese Ore at the Visakhapatnam Port Trust (VPT) relating to M/s. S.K. Sarawagi & Co. (P) Limited and M/s. Ram Bahadur Thakur Limited. This Order was notified in the Gazette of India Extraordinary (Part-III Section 4) on 31 December, 99 vide Gazette No. 112.

2. There is a typographical error in paragraph No. 22.1 of the Order. In the last sentence of the paragraph the rate of interest has been given as '@ 24% per annum' instead of '@ 12% per annum'. The last sentence of paragraph No. 22.1 is, therefore, deleted and substituted by the following :—

"The VPT is required to rework the handling costs accordingly in the cases of the Applicants and made the necessary refunds alongwith interest @ 12% per annum as directed by the Supreme Court".

S. SATHYAM, Chairman

[Advt. III/IV/Ext.y./143/99]

